नईदुनिया

ईरान से तनाव के बीच जर्मनी में हुई 8 देशों के सैन्य प्रमुखों की बैठक, सेंटकाम ने की मेजबानी

वाशिंगटन

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकाम) ने पिछले सप्ताह जर्मनी में एक बैठक के दौरान आठ देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मेज़बानी की। एक अमेरिकी अधिकारी ने अनादोलु को बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करना था।

अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के संभावित तरीकों पर विचार किया गया। हालांकि, उन्होंने इसमें शामिल देशों और चर्चा किए गए विशिष्ट मुद्दों की जानकारी देने से इनकार कर दिया।

तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू के मुताबिक, अमेरिकी समाचार आउटलेट एक्सियोस ने दो इज़राइली अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि बैठक में इज़राइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, कुवैत, कतर, जार्डन और मिस्र के सैन्य प्रमुख शामिल हुए थे। हालांकि, अमेरिकी अधिकारी ने इन देशों की भागीदारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की।

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटकाम प्रमुख जनरल ब्रैड कूपर ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को बताया कि ईरानी हमलों के बावजूद अमेरिकी सेना मध्य पूर्व से अपनी सैन्य मौजूदगी कम नहीं करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कूपर ने प्रतिभागियों को होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही बढ़ाने की अमेरिकी योजनाओं की जानकारी दी। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। जून में दोनों पक्षों के बीच एक समझौते से जुड़े मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर होने की बात सामने आई थी, जिसमें इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलने की योजना का उल्लेख था। इसी दौरान क्षेत्र में हूथी बलों की गतिविधियां भी बढ़ने की खबरें सामने आईं। रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब पर हमले तेज हुए और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं। फरवरी में अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था। हमलों में सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों, मिसाइल ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए। इसके बाद संघर्ष का असर मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला। इस पृष्ठभूमि में जर्मनी में हुई सेंटकाम की बैठक को क्षेत्रीय सैन्य सहयोग और सुरक्षा समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यूज़ब्रीफ

नेपाल में मातृत्व अवकाश 90 दिन से बढ़ाकर 6 महीने करने की तैयारी, पिता को 42 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव

काठमांडू। नेपाल सरकार मातृत्व और पितृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, माताओं को मिलने वाले मौजूदा 90 दिनों के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 6 महीने किया जाएगा। वहीं, पिता के लिए वर्तमान 15 दिनों के अवकाश को बढ़ाकर 42 दिन करने का प्रस्ताव है। कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों की मंत्री सोविता गौतम के अनुसार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम, 2018 में संशोधन के लिए विधेयक तैयार कर लिया गया है। अब मंत्रालय इसे मंत्रिपरिषद के माध्यम से संसद में पेश करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित विधेयक में मां को कम से कम 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश और पिता को 42 दिनों तक वेतन सहित प्रसूति देखभाल अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व और अभिभावकत्व के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव होगा। मंत्रालय के अनुसार, व्यस्त जीवन, काम के बढ़ते दबाव और बदलती जीवनशैली के कारण अधिकांश परिवार अब एक या दो बच्चों तक ही सीमित हो रहे हैं। ऐसे में माता-पिता को नवजात शिशु और परिवार के साथ पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया है। मंत्री सोविता गौतम ने कहा कि मातृत्व जीवन में एक या दो बार आने वाला विशेष समय है और इस दौरान माता-पिता को अपने नवजात बच्चे तथा परिवार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देना मां से जुड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बच्चे का पालन-पोषण केवल मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माता-पिता की साझा जिम्मेदारी है।

दिव्यांग बेटे के लिए 80,000 प्लास्टिक बोतलों से बना आशियाना

ढाका। प्लास्टिक की खाली बोतलें, जिन्हें अक्सर कूड़ा मानकर फेंक दिया जाता है, वही बांग्लादेश के एक दंपति के लिए न केवल एक घर बनाने का माध्यम बनीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण भी बन गईं। लालमोनिरहाट जिले के एक दूरदराज गांव में राशेदुल आलम और असमा खातून ने लगभग 80 हजार प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर 1700 वर्ग फुट का एक विशाल घर बनाया है। उनके इस असाधारण कदम का मुख्य उद्देश्य अपने दिव्यांग बेटे के लिए एक सुरक्षित और अलग तरह का आशियाना तैयार करना था, साथ ही यह संदेश देना भी था कि प्लास्टिक कचरे का रचनात्मक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। 2017 में निर्मित यह घर आज भी प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने और टिकाऊ निर्माण के तरीके सिखाने का एक जीवंत प्रतीक है। राशेदुल और असमा, दोनों पर्यावरण विज्ञान के छात्र रहे हैं। अपने दिव्यांग बेटे के लिए एक ऐसे घर की कल्पना की जो न केवल कार्यात्मक हो, बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो। उनकी यह पहल बांग्लादेश में अपनी तरह की पहली थी। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी के आर्किटेक्चर विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने भी इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक अभिनव और सराहनीय प्रयास बताया, जो पारंपरिक निर्माण सामग्री पर निर्भरता को कम करता है। इस अनूठी परियोजना को साकार करने के लिए दंपति ने हजारों प्लास्टिक बोतलों में रेत भरी। ये रेत भरी बोतलें ही उनकी दीवारों की मूल इकाई बनीं।

अमेरिकी विदाई के बाद इराकः मिलिशिया की चुनौती और अनिश्चित भविष्य

वाशिंगटन। अमेरिका इराक में अपनी 23 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी का अंत करने वाला है। 30 सितंबर तक उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र से बचे सैकड़ों अमेरिकी सैनिक पूरी तरह देश छोड़ देने वाले हैं, और इराक में लगे एयर डिफेंस सिस्टम भी हटाए जो रहे हैं। 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी आक्रमण के बाद से इराक में उसकी सैन्य उपस्थिति बनी हुई थी, जो 2011 में वापसी के बावजूद 2014 में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के उभरने के कारण फिर से स्थापित हुई। अब जबकि आईएसआईएस सिर्फ बिखरे स्लीपर सेल्स तक सीमित रह गया है, अमेरिका इराक से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। लेकिन वापसी ने इराक में एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। ईरान समर्थित शक्तिशाली बागी मिलिशिया ने साफ चेतावनी दी है कि उनके हमले जारी रहने वाले है। इराकी सरकार ने अमेरिकी सैनिकों के जाने को इन गैर-सरकारी समूहों के निरस्त्रीकरण से जोड़ा है। हालांकि, कतैब हिजबुल्लाह, हरकत अल-नुजाबा और कतैब सय्यिद अल-शुहदा जैसे सबसे शक्तिशाली ईरान समर्थित संगठन हथियार छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

बांग्लादेश : डीयूसीएसयू विवि में जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन

ढाका

ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (डीयूसीएसयू) के नवीनीकृत म्यूज़ियम/आर्काइव में पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें लगाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। तस्वीरों के प्रदर्शन का छात्र संगठनों ने विरोध किया। विरोध के दौरान जिन्ना की एक तस्वीर और उनसे संबंधित अखबार की क्लिपिंग को फाड़कर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश छात्र फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने उसी स्थान पर जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अमीर गुलाम आज़म की 1981 में पिटाई की तस्वीर लगा दी।

डीयूसीएसयू ने रिनोवेशन के बाद म्यूज़ियम को दोबारा खोला था। इसमें जिन्ना से संबंधित तीन नई सामग्री शामिल की गई थीं। इनमें 21 मार्च 1948 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में जिन्ना के भाषण की तस्वीर, 1940 के लाहौर अधिवेशन की तस्वीर और 1970 के चुनाव से संबंधित डान अखबार की क्लिपिंग शामिल थी। 1948 के भाषण में जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की एकमात्र राजभाषा बनाने की घोषणा की थी।

म्यूज़ियम में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की कोई अलग या प्रमुख तस्वीर नहीं रखी गई थी। हालांकि, उनके बेटों की 1974 की शादियों से संबंधित एक तस्वीर और शेख मुजीब पर प्रकाशित तीन अखबारी क्लिपिंग प्रदर्शनी में मौजूद थीं।

ढाका यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के छात्र मोहम्मद अबू तैयब, जिन्हें हबिलडर के नाम से भी जाना जाता है, म्यूज़ियम पहुंचे और जिन्ना की एक तस्वीर को फ्रेम से निकालकर नष्ट कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या डीयूसीएसयू के घोषणापत्र में जिन्ना को नायक के तौर पर प्रस्तुत करने की बात कही गई थी और भाषा आंदोलन तथा 1971 के मुक्ति संग्राम के इतिहास का हवाला दिया।

बांग्लादेश छात्र फेडरेशन की ढाका यूनिवर्सिटी इकाई के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर वाली जगह पर गुलाम आज़म की 1981 में बैतुल मुकर्रम के बाहर पिटाई की तस्वीर लगा दी।

फेडरेशन के आयोजन सचिव अर्को बरुआ ने कहा कि डीयूसीएसयू किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है और इतिहास को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह डीयूसीएसयू की लिबरेशन वार एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट अफेयर्स की सचिव फातिमा तस्नीम जुमा ने अपनी इच्छा के अनुसार जिन्ना की तस्वीर लगाई, उसी तरह उन्होंने गुलाम आज़म की तस्वीर लगाई।

डीयूसीएसयू की लिबरेशन वार एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट अफेयर्स की सचिव फातिमा तस्नीम जुमा ने कहा कि जिन्ना की तस्वीरें उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं लगाई गई थीं। उनके अनुसार, तस्वीरें 1905 से 1971 तक ढाका यूनिवर्सिटी के इतिहास को समझाने के उद्देश्य से जानकारीपूर्ण कैप्शन के साथ प्रदर्शित की गई थीं।

डीयूसीएसयू के महासचिव एसएम फरहाद ने भी इसी तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि जिन्ना के 1948 के भाषण को शामिल करने का उद्देश्य उनके बांग्लादेश-विरोधी रुख को दिखाना था, न कि उसका महिमामंडन करना। उनका कहना था कि इतिहास के किसी हिस्से को छिपाने से उसे समझने में मदद नहीं मिलेगी।

बांग्लादेश जातीयतावादी छात्र दल (जेसीडी) ने भी जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने का विरोध किया। संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह का प्रदर्शन भाषा आंदोलन और मुक्ति संग्राम के इतिहास के अनुरूप नहीं है। संगठन ने तस्वीर हटाने और डीयूसीएसयू को किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रचार का मंच नहीं बनाने की मांग की।

बांग्लादेश छात्र संघ के एक गुट ने भी जिन्ना की तस्वीरों पर आपत्ति जताते हुए शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को दोबारा प्रदर्शित करने की मांग की। संगठन ने कहा कि मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता की तस्वीर हटाना इतिहास की प्रस्तुति को प्रभावित करता है।

विवाद के बीच ढाका यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि डीयूसीएसयू की हाल की कई गतिविधियां विश्वविद्यालय के नियमों और प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप नहीं थीं।

प्रशासन के मुताबिक, इनमें विश्वविद्यालय के सिंडिकेट या कुलपति की मंजूरी के बिना डीयूसीएसयू भवन के पास निर्भीक जुलाई स्मारक स्थापित करना, म्यूज़ियम में जिन्ना और पूर्व छात्र नेता अब्दुल मलिक की तस्वीरें प्रदर्शित करना तथा शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए एक अलग वेबसाइट शुरू करना शामिल है।

विश्वविद्यालय ने कहा कि डीयूसीएसयू छात्रों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि निकाय है, लेकिन उसे विश्वविद्यालय के मौजूदा कानूनों, नियमों, नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ही काम करना होगा। प्रशासन ने किसी भी तरह का समानांतर प्रशासनिक ढांचा बनाने के प्रयास का विरोध करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कुलपति डा. एबीएम ओबैदुल इस्लाम ने भी कहा कि डीयूसीएसयू ने विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ काम किया है। इस बीच, जिन्ना की तस्वीरें नष्ट किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क के सदस्यों ने भी डीयूसीएसयू आर्काइव का दौरा किया। दूसरी ओर, बांग्लादेश स्टूडेंट्स यूनियन के विभिन्न गुटों ने अलग-अलग बयानों में जिन्ना की तस्वीरें प्रदर्शित किए जाने पर आपत्ति जताई और म्यूज़ियम में इतिहास की प्रस्तुति को लेकर अपनी मांगें रखीं।

नेपाल : बाढ़ के 21वें दिन भी तलाश जारी, 1,399 शव मिले 5,179 लोग अब भी लापता

काठमांडू

नेपाल में गत 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के 21वें दिन भी खोज और राहत अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1,399 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5,179 लोग अभी भी लापता हैं।

करीब 21 हजार सुरक्षाकर्मी अब भी खोज, बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं। जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों, नदी के किनारों, आसपास के जंगलों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजाराम बस्नेत के अनुसार सेना के करीब 8,900 जवान सीधे खोज, बचाव और समन्वय कार्यों में तैनात हैं।

सशस्त्र पुलिस के करीब 5,000 जवान भी अभियान में शामिल हैं। इनके द्वारा बचाव अभियान चलाने के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल पुलिस के करीब 8,000 जवान भी खोज और बचाव कार्य में लगाए गए हैं। बाढ़ में रसुवा और नुवाकोट स्थित नेपाल पुलिस के पांच कार्यालय भी बह गए थे, जिन्हें अभी तक पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका है।

रसुवा के स्याफ्रुबेसी क्षेत्र में खोज और बचाव के लिए सेना की तीन टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ में स्याफ्रुबेसी बाजार का बड़ा हिस्सा बह गया था और वहां पहुंचने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत एवं खोज अभियान में देरी हुई।

सेना प्रभावित कोलोनी, तुप्चे, दानसिंग, सामरी भंज्यांग, कालिकास्थान और मानचेत समेत कई इलाकों में पैदल गश्त भी कर रही है। दुर्गम और सड़क संपर्क से कटे इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। नेपाली सेना के ड्रोन से नुवाकोट में 16,138 किलोग्राम और रसुवा में 5,861 किलोग्राम राहत एवं आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा चुकी है।

चीन सीमा से लगे प्रमुख व्यापारिक बाजार टिमुरे में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। सशस्त्र पुलिस की बीओपी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी कार्यालय बह गए हैं। तीन सप्ताह बीतने के बाद भी सशस्त्र पुलिस के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियां वहां पूरी तरह नहीं पहुंच सकी हैं। टिमुरे बाजार से 100 से अधिक शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाढ़ से ध्वस्त मकानों में अब तक खुदाई शुरू नहीं हो पाई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेपाल पुलिस की मौजूदगी नहीं होने के कारण भी खुदाई और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

नेपाल के मुगु जिले में ढाई घंटे के अंतराल में दो बार आया भूकंप, 4.5 और 4.2 रही तीव्रता

काठमांडू। नेपाल के मुगु जिले को केंद्र बनाकर तड़के करीब ढाई घंटे के अंतराल में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप मापन एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, मुगु के कालै क्षेत्र को केंद्रबिंदु बनाकर रात 1 बजकर 51 मिनट पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद सुबह 4 बजकर 28 मिनट पर उसी स्थान के आसपास 4.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप दर्ज किया गया। केंद्र के वरिष्ठ भूकंपविद् डा. लोकविजय अधिकारी ने बताया कि दोनों भूकंपों के बीच करीब ढाई घंटे का अंतर था। उन्होंने कहा कि 4.5 और 4.2 तीव्रता के भूकंप से आमतौर पर बड़ी क्षति की संभावना कम होती है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। अधिकारी के अनुसार, हर बड़े भूकंप के बाद पराकंप (आफ्टरशाक) आते हैं। 4 तीव्रता का भूकंप आने वाले क्षेत्र में भी इसके बाद 3, 2 और 1 तीव्रता के कई छोटे भूकंप आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह मुस्तांग जिले में आए भूकंप के बाद अब तक करीब 20 से 22 परकंप दर्ज किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि, बीते 8 सितंबर की रात 9:53 बजे मुस्तांग में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके झटके काठमांडू में भी महसूस किए गए थे।

ईरानी टैंकरों पर हमले के कारण चीन की तेल आपूर्ति पर मंडराया संकट

होर्मुज में तेल-एलपीजी के टैंकर डुबो रहा अमेरिका

बीजिंग

अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए जो योजना तैयार की है, वह अब प्रभावी होती दिख रही है। ईरान का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीददार चीन रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले लगभग एक दशक से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध चीन को ईरान से तेल खरीदने से पूरी तरह रोकने में सफल नहीं हो पाए थे। चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद कम कीमत पर ईरानी तेल खरीदने के रास्ते तलाश लिए थे, लेकिन अब ईरानी तेल टैंकरों को अमेरिकी मिसाइलों से निशाना बनाए जाने के बाद स्थिति तेजी से बदल रही है।

एक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी नौसेना ने खार्ग द्वीप से तेल लोड कर रहे एक ईरानी टैंकर को निशाना बनाया है। खार्ग द्वीप वह प्रमुख केंद्र है, जहां से ईरान के लगभग 90 प्रतिशत तेल निर्यात की लोडिंग होती है। विश्लेषण के मुताबिक, यह पहली बार है जब अमेरिका ने केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बजाय, उस भौतिक आपूर्ति श्रृंखला को सीधे निशाना बनाया है, जिसके जरिए

ईरान का तेल चीन की रिफाइनरियों तक पहुंचता है। यह कदम चीनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है।

ईरान से मिलने वाला सस्ता तेल चीन की छोटी और स्वतंत्र रिफाइनरियां बड़े पैमाने पर खरीदती हैं, जिन्हें आमतौर पर टीपाट रिफाइनरी कहा जाता है। ये रिफाइनरियां चीन में पेट्रोलियम उत्पादों के कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा रखती हैं। इन रिफाइनरियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन की अपनी भुगतान व्यवस्था और डालर से अलग भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वे ईरान से उपलब्ध बड़ी मात्रा में तेल खरीदने में सफल रहीं। हालांकि, अब टैंकरों पर सीधे हमले से इनके सामने नई समस्या खड़ी हो गई है।

अगर तेल ले जाने वाले जहाज ही नष्ट हो जाते हैं, तो केवल वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम के सहारे आपूर्ति जारी रखना संभव नहीं होगा। समुद्र में डूब चुके जहाजों को चीन तुरंत वापस भी नहीं ला सकता, जिससे आपूर्ति में तत्काल बाधा आएगी। यह स्थिति चीन के लिए और भी चिंताजनक है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी अशांति के कारण वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता पहले ही कम हुई है।

बाढ़ के कारण रसुवागढी-केरुंग सीमा नाका बंद होने के बाद चीन ने तातोपानी नाका भी बंद किया

काठमांडू

नेपाल-चीन के प्रमुख व्यापारिक नाके रसुवागढी-केरुंग के बाढ़ के कारण बाधित होने के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण सीमा नाका तातोपानी के संचालन को भी बंद कर दिया गया है। चीन की ओर से नाका कब खोला जाएगा, इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी गई है।

रसुवागढी-केरुंग नाका बंद होने के तुरंत बाद चीन ने नेपाल को पत्र भेजकर तातोपानी नाका भी अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी थी। हालांकि, नाका बंद करने का कारण चीनी पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया है।

ल्हासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत लक्ष्मीप्रसाद निरौला ने बताया कि उन्हें तातोपानी नाका बंद किए जाने का कारण और इसे दोबारा खोलने की तारीख की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि रसुवागढ़ी नाका बंद होने के बाद केरुंग में फंसे नेपाली पर्यटकों और मालवाहक कंटेनरों को तातोपानी तथा कोरला नाके के रास्ते नेपाल लाने के लिए चीन से अनुरोध किया गया था। पर्यटकों को तातोपानी नाके से लौटने की अनुमति दी गई, लेकिन मालवाहक कंटेनरों को अनुमति नहीं मिली।

निरौला के अनुसार, रसुवागढी नाका बंद होने की स्थिति में यदि तातोपानी और कोरला दोनों नाकों का इस्तेमाल किया जा सके तो नेपाल-चीन व्यापार को काफी सुविधा होगी। इसके लिए चीन से औपचारिक अनुरोध किया गया है, लेकिन तातोपानी नाका खोलने के संबंध में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

चीन ने 31 अगस्त को पत्र भेजकर तातोपानी नाका अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी थी। इस बीच, 4 सितंबर को चाइना डेली ने खबर दी थी कि चीन नेपाल के साथ प्रमुख स्थल व्यापारिक नाका झांगमु में सीमा जांच और सीमा शुल्क से संबंधित व्यवस्थाओं में बदलाव करने जा रहा है।

स्थानीय सरकार के अनुसार, उच्च हिमाली

क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा जांच व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। झांगमु नाका शिगात्से के अंतर्गत सिजांग स्वायत्त क्षेत्र के न्यालाम में स्थित है।

नई व्यवस्था के तहत नेपाल-चीन सीमा पार करने वाले यात्रियों को केवल निर्धारित मार्गों से ही आवागमन की अनुमति होगी। वे निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे और रास्ते में अपनी इच्छा से वाहन में चढ़ने-उतरने या निर्धारित स्थान के अलावा अन्य लोगों से संपर्क करने पर भी रोक होगी।

बिना अनुमति नियंत्रित सड़क खंडों पर वाहन रोकने, यात्रियों को चढ़ाने-उतारने तथा माल लोड या अनलोड करने की भी अनुमति नहीं होगी। सीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं होने वाले लोगों और वाहनों को भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

तातोपानी सीमा शुल्क कार्यालय के प्रमुख दीपेन्द्र प्रकाश गिरी ने बताया कि 8 सितंबर से तातोपानी नाके से मालवाहक कंटेनरों की क्लीयरेंस नहीं हुई है। हालांकि, यात्री वाहनों को आने-जाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने भी नाका बंद किए जाने का कारण स्पष्ट जानकारी में नहीं होने की बात कही।

रसुवागढी नाका बाधित होने और तातोपानी नाका बंद होने के बाद नेपाल-चीन के स्थल व्यापार के लिए फिलहाल मुस्तांग के कोरला नाके का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, कोरला नाका काठमांडू से रसुवागढी और तातोपानी की तुलना में काफी दूर है। कोरला से काठमांडू की दूरी करीब 481 किलोमीटर, काठमांडू-तातोपानी करीब 124 किलोमीटर और काठमांडू-रसुवागढी करीब 160 किलोमीटर है। इसके अलावा कोरला से केरुंग की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ के सचिव भक्त पराजुली के अनुसार, दूरी, लागत, समय और बुनियादी ढांचे समेत कई कारणों से चीन के साथ व्यापार के लिए तातोपानी नाका कोरला की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। उन्होंने बताया कि केरुंग से कोरला पहुंचने में ही करीब एक दिन लगता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी के कारण सीमा शुल्क की प्रक्रिया भी एक दिन में पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद सड़क की स्थिति और वाहनों के कारण काठमांडू तक सामान पहुंचने में करीब तीन दिन और लगते हैं।